सिंचाई आंकड़ों में परिवर्तन

2616. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई, 1994 के ''इकोनामिक टाइम्स'' में ''लार्ज स्केल चेन्जिज इन इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स कम्पलेंट एक्स-आफिशियल्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में सिंचाई क्षमता पैदा होने तथा सिंचाई क्षमता की उपयोगिता की मात्रा से संबंधित आंकड़ों में पिछले कई वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों में विभिन्नता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में सिंचाई क्षमता तथा इसकी उपयोगिता की मात्रा के संबंध में सरकार की नवीनतम सूचना क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। योजना आयोग के कहने पर राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर अधिक सूचित और अन्य अशुद्धियों को ठीक करने के वास्ते वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सृजित व उपयोग की गयी सिंचाई क्षमता का पुन: आंकलन छठी योजना के अंत में किया गया था। छठी योजना के अंत में सृजित की गयी क्षमता एवं उसके उपयोग के पहले सूचित किए गए क्रमश: 30.01 मिलियन हेक्टेयर और 25.33 मिलियन हेक्टे. के आंकड़ों के स्थान पर क्रमश: 27.70 मिलियन हेक्टेयर एवं 23.57 मिलियन हेक्टेयर सम्पुष्ट किए गये। इस प्रकार अब सुदृढ़ किये गये संशोधित आंकड़ों को स्वीकार कर लिए जाने के कारण रिपोर्टों में उल्लिखित आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है।

(घ) 1993-94 के अंत में वृहद व मझौली एवं लघु योजनाओं के माध्यम से सृजित की गयी कुल सिंचाई क्षमता एवं उसके उपयोग का आंकलन क्रमश: लगभग 85.05 मिलियन हेक्टेयर और 76.27 मिलियन हेक्टेयर लगाया गया है।

निर्माणाधीन परियोजनाएं

2617. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1994 के अंत तक देश में अनेक सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है तथा प्रत्येक परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं में ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है, जिनमें कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(घ) निर्माण कार्य में हुए विलंब के कारण उन परियोजनाओं की निर्माण लागत में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ङ) उन सभी चालू अथवा निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कुल कितनी अनुमानित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) 158 वृहद, 226 मध्यम और 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण (ई आर एम) परियोजनाएं क्रमश: 54,470 करोड़ रुपए 4,797 करोड़ रुपए और 6,309 की अनुमानित लागत पर आठवीं योजना में आगे ले जाई गई।

(ग) और (घ) उपर्युक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 103 वृहद, 165 मध्यम और 20 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इनमें से 92 वृहद, 159 मध्यम और 17 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही है। उनकी लागत क्रमश: लगभग 600% , 400% और 200% बढ़ गई है।

(ङ) सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने पर सृजित की जाने वाली अनुमानित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 2,48,12,000 हेक्टेयर होने की संभावना है।

National Policy on Allocation of Available Water Resources

2618. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI SATISH AGARWAL:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that since achieving independence. Government have not so far been able to formulate any National Policy for

allocation of available water resources in the country;

(b) whether the meetings held between the National Water Board (NWB) and the National Water Resources Council (NWRC) have given any clear-cut guidelines; and

(c) if so, how does the Central Government propose to intervene without being a party or using overriding powers over the co-basin States which continue to have dispute for allocation of available water resources, and at the same time keeping in view the national interest and needs dictated by international relations/obligations as well as'those of National Waterways for navigation etc., showing the latest progress made in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Under Entry 56 of the List I of the Seventh scheduled of the Constitution adopted in 1950, Parliament has overriding power of legislation for regulation of inter State rivers and river valleys in the public interest. Under Article 262 of the Constitution, adjudication of any dispute or complaint in respect to the use, distribution or control of water of any inter-State river or river valley is provided for. The Inter- State Water Dispute Act of 1956 has already been enacted for this purpose, and has been amended from time to time. The River Board Act of 1956 was also enacted simultaneously under Entry 56 of the Constitution. Under the Inter-State Water Dispute Act of 1956, tribunals were set up for allocation of waters of inter-state rivers of Krishna, Godavari, Narmada, Ravi, Beas and Cauvery. However, there were no guidelines in these Acts for sharing or allocations of inter-State river waters. While adopting the National Water Policy in its second meeting held in September, 1987, the National Water Resources Council had taken note of the need for formulating proper guidelines for water allocation of inter-State rivers amongst the States. A draft national policy guidelines for water allocation of inter-State rivers amongst States framed recently has been circulated to the State Governments and was also discussed in the meetings of the National Water Board held in June, 1994 in which the States and Union Territories are represented/The modified draft, based on the discussions in National Water Board, has been circulated to the States and included in the agenda for the next meeting of National Water Resources Council.

(c) The draft guidelines lay down that all the co-basin States and Central Government would be parties to the process of water allocation. In the process of Water alloction, the Central Government would take care of water allocations required in the National interest. The National interest may, inter-alia, include water required from environmental and ecological considerations of the rivers, estuary and the sea, water required for maintaining proper navigation in the National Waterways and the water required for meeting international obligation for maintaining good international relations.

People Ousted due to Sardar Sarovar Project

2619. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the total number of people ousted due to Sardar Sarovar Project in Gujarat as on date;

(b) whether Government have drawn up any scheme for their rehabilitation, if so the details thereof;

(c) number of persons resettled as a result of the implementation of the scheme and where; and

(d) by when all the oustees are likely to be rehabilitated?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) The number of families ousted in Gujarat due to Sardar Sarovar Project is 4600.

(d) The State Government of Gujarat have drawn up Action Plan for Resettlement and Rehabilitation of the Project Affected Families in Gujarat as per the State's policy which include allotment of agricultural land to the landed oustees, encroachers, landless oustees and major sons; house plots to the oustee